नाबार्ड

अध्यक्ष की कलम से...

भारत ने 2024-25 में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार व्यवधानों से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण वैश्विक पृष्ठभूमि में भी अपनी अनुकूलन-क्षमता प्रदर्शित करते हुए जीडीपी में 6.5% की वृद्धि हासिल की है. इस प्रदर्शन में सुदृढ़ समष्टिगत वित्तीय बुनियादी सिद्धांतों अर्थात् मुद्रास्फीति को सामान्य बनाए रखने, अच्छे कॉर्पोरेट स्वास्थ्य, स्थिर वित्तीय प्रणाली और संधारणीय बाह्य क्षेत्र का सहयोग रहा है. यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण माँग के मजबूत होने और बेहतर ऋण प्रवाह के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र ने सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में उल्लेखनीय गति दिखाई.

केंद्रीय बजट 2025-26 में, निवेश, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समग्रतामूलक कार्यक्रम "ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन-क्षमता" की घोषणा की गई जिससे समावेशी ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने, दलहन और खाद्य तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर होने, आपूर्ति शृंखला की दक्षता में सुधार और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने पर नीतिगत बल दिया जा रहा है.

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत की शीर्ष विकास वित्त संस्था के रूप में, नाबार्ड ने इन उभरती प्राथमिकताओं को गतिशील और सकारात्मक प्रतिसाद दिया. हमने न केवल पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाने, वित्तीय समावेशन को गहन बनाने, ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने जैसे रणनीतिक सहयोगों पर बल दिया, बल्कि अपने कार्यक्रमों और नीतियों को भी सक्रियता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलती प्राथमिकताओं और उभरती ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित किया.

वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण ₹27.5 लाख करोड़ के निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए ₹28.7 लाख करोड़ के नए शिखर पर पहुँच गया, जिससे इस क्षेत्र की ऋण सघनता और बढ़ी और कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन के 53% तक पहुँच गई. नाबार्ड द्वारा रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाना एक प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से नाबार्ड इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देता है. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने ₹1.9 लाख करोड़ की राशि अल्पावधि पुनर्वित्त और ₹1 लाख करोड़ की राशि दीर्घावधि पुनर्वित्त के रूप में संवितरित की. ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास का वित्तपोषण नाबार्ड के विकासलक्षी सहयोग का सबसे प्रमुख घटक है, जो ग्रामीण संपर्क और बाजार पहुँच में वृद्धि के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कृषीतर गतिविधियों का

संवर्धन करने में योगदान करता है. वित्तीय वर्ष 2025 तक ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए ₹6.8 लाख करोड़ का संचयी संवितरण किया गया.

नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के संस्थागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जिससे आधार स्तर पर वित्तपोषण सुलभ हुआ और परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाने में सहयोग मिला. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने अपनी अभिशासन प्रणालियों को और मजबूत बनाने, व्यवसाय विविधीकरण को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन और जोखिम प्रबंधन की क्षमताओं का निर्माण करने तथा व्यवसाय पहुँच में विस्तार करने का प्रयास किया. 'उन्नति चरण II' पहल के अंतर्गत नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) एक्सेलरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया ताकि ऋणेतर व्यावसाय गतिविधियों को विविधीकृत करने के लिए पैक्स को सक्षम बनाया जा सके. प्रायोगिक चरण में, इस कार्यक्रम को 30 समितियों में कार्यान्वित किया जा रहा है, और इसे 10,000 पैक्स तक बढ़ाने की योजना है. पैक्स के लिए एक साझा सेवा संस्था (एसएसई) स्थापित करने में नाबार्ड एक प्रमुख हितधारक है. इस संस्था का उद्देश्य व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी-संचालित और किफ़ायती सहयोग सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध कराकर पैक्स की संस्थागत और वित्तीय संधारणीयता को और बल प्रदान करना है.

वित्तीय समावेशन को गहराई तक ले जाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने क्षमता निर्माण, ऋण सुविधा और बाजार लिंकेजों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह और कृषक उत्पादक संगठन जैसी आधार स्तर की संस्थाओं को सशक्त बनाने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है. वित्तीय वर्ष 2025 में स्वयं सहायता समूह – बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 55.6 लाख स्वयं सहायता समूहों को ₹2.1 लाख करोड़ का ऋण संवितरित किया गया और बैंकों द्वारा 49.8 लाख संयुक्त देयता समूहों को सहयोग दिया गया. नाबार्ड महिला स्वयं सहायता समूहों को समर्थ बनाने की दृष्टि से तैयार किए गए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी एकीकरण और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी जैसी अग्रगामी योजनाओं के साथ भी अपने प्रयासों का तालमेल बिठा रहा है.

नाबार्ड सीमांत और लघु कृषकों की मोलभाव की क्षमता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों के गठन में सहायता दे रहा है. वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण, बाजार एकीकरण और सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल के माध्यम से कृषक उत्पादक संगठनों के लिए मजबूत संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के अपने प्रयासों के अंतर्गत नाबार्ड ने 31 मार्च 2025 तक संचयी रूप से 7,439 एफपीओ के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है.

ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के समावेशी विकास की कहानी के केंद्र में हैं, जो कृषीतर रोज़गार सृजन, ग्रामीण उद्यमिता और नवोन्मेष के संवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं. स्टार्ट-अप ग्रामीण भारत में रूपांतरकारी बदलाव ला रहे हैं, एक ओर वे भारत की मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने नवोन्मेषी समाधानों से जलवायु संबंधी आघातों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का समाधान उपलब्ध करा रहे हैं. नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिवर्तन ला रहा है, ताकि उभरते अवसरों का दोहन किया जा सके और एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके. संरचित प्लेटफार्मों के महत्व को मान्य करते हुए, जो मापने योग्य सामाजिक परिणामों के साथ उद्यमों को पूँजी उपलब्ध कराते हैं, नाबार्ड ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) का सफलतापूर्वक प्रयोग शुरू किया है. यह एक अनोखी पहल है जो नाबार्ड को वित्त और सामाजिक प्रभाव के मिलन-बिंदु पर रखती है. इसने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए विचारों को प्रभावी तरीके से लाभप्रद व्यवसाय मॉडलों के रूप में परिवर्तित करने को संभव बनाने के लिए वर्ष के दौरान तीन नए ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्रों (आरबीआईसी) की स्थापना को मंजूरी दी, जिससे मंजूर केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई, जिनमें से 9 केंद्र 31 मार्च 2025 की स्थिति में कार्य कर रहे थे.

पर्यावरणीय संधारणीयता आर्थिक विकास के एक नए महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभरी है, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम शमन और अनुकूलन दोनों पर नीतिगत स्तर पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है. नाबार्ड संधारणीयता कार्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक प्रखर और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के प्रस्ताव और समर्थन के क्षेत्र में एक विचारक के रूप में उभर रहा है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड ने अपनी जलवायु रणनीति 2030 आरंभ की जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है - हरित ऋणीकरण में

तेजी, बाजार निर्माण, आंतरिक हरित रूपांतरण और रणनीतिक संसाधन संग्रहण. नाबार्ड हरित ऋणीकरण सुविधा (एनजीएलएफ़) की शुरुआत ने जलवायु वित्त के क्षेत्र में हमारे प्रवेश को और मज़बूती दी है. जलवायु कार्रवाई के संबंध में संस्थागत क्षमता और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हरित साक्षरता मॉड्यूल भी शुरू किए गए हैं.

मार्च 2025 के अंत की स्थिति में ₹9.8 लाख करोड़ के तुलन पत्र और बाजार से उधार ली गई धनराशि के बढ़ते मिश्रण के साथ, नाबार्ड ने ग्रामीण विकास की बहु-आयामी प्रकृति को पहचानते हुए और विकास के अपेक्षित प्रभाव के सृजन उत्पन्न करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हुए आस्ति-विस्तार-सह- विविधीकरण की रणनीति अपनाई है. 1 अप्रैल, 2024 से अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर बेसल III विनियामक ढाँचे के लागू होने के बाद, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में आवश्यक परिवर्तनों को अपनाते हुए इस संक्रमण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे विकास कार्यक्रमों के आयोजना और कार्यान्वयन के समय परिचालन की वित्तीय सुदृढ़ता पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ता की रक्षा के लिए, नाबार्ड निर्णायक रूप से जोखिम-आधारित अनुप्रवर्तन की ओर बढ़ रहा है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम-भारित आस्तियों में पूँजी अनुपात समेकित रूप से 14.4% के साथ अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया, और उनकी आस्तियों की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जैसा कि उनकी सकल अनर्जक आस्ति के कम होकर 5.3% हो जाने से स्पष्ट है, जो पिछले 13 वर्षों में सबसे कम है. 'एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के लक्ष्य से प्रेरित, वर्ष के दौरान शुरू हुए समामेलन के चौथे चरण से यह उम्मीद है कि आगे चलकर देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहले से ज़्यादा मज़बूत और अधिक प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित हो सकेगी.

इस वर्ष नाबार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही ग्रामीण भारत महोत्सव (जीबीएम) का आयोजन जिसमें भारत की ग्रामीण उद्यमशीलता की शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित किया गया. इस आयोजन ने जमीनी स्तर पर नाबार्ड के माध्यम से लाए गए विकासात्मक प्रभावों की व्यापक शृंखला को प्रदर्शित किया और एक अधिक समृद्ध ग्रामीण भारत के साथ विकसित भारत के विज़न को साकार करने के हमारे दृढ़ संकल्प को सामने रखा.

गतिशील समष्टिगत वित्तीय परिवेश में, आकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों की हमसे बढ़ती अपेक्षाओं को समझते हुए, निरंतर सीखने और नवोन्मेष की मानसिकता के साथ स्वयं को उनके अनुरूप तैयार करते रहना होगा.

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सभी राज्य सरकारों, हमारे मूल्यवान बैंकिंग साझेदारों, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं, सहकारी समितियों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य विकास सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका विश्वास और भागीदारी हमें प्रेरित करती है और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है.

मुझे विश्वास है कि हमारी समर्पित टीमों, मजबूत साझेदारियों और हमारे मिशन की प्रेरक शक्ति के साथ, नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास करता रहेगा.

शाजी के.वी.
अध्यक्ष